तथा स्थल पर पहुंचना कठिन हो जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था। तदनुसार रेलवे द्वारा दी गई स्वीकृति समाप्त हो गई। आवश्यक स्वीकृति देने के लिए रेलवे से पुनः प्रार्थना की गई है। इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं।

Implementation of Additional Employment Programme in West Bengal

5632. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Government of West Bengal implemented additional employment Programme with an outlay of Rs. 459.12 lakhs against the total outlay of Rs. 358.67 lakhs as approved by the Planning Commission;

(b) whether the State Government have already requested the Central Government to accord approval to the revised outlay; and

(c) if so, the action taken thereon?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) Under the Empolyment Promotion Programme (1974-75) financed by the Central Government, scheme requiring a total outlay of Rs. 358.67 lakhs recommended from West Bengal were sanctioned after scrutiny.

(b) The Government of West Bengal later reported a total expenditure of Rs. 459.12 lakhs and requested *ex post facto* sanction of this amount for reimbursement.

(c) The State Government has been informed that the Central Government is unable to agree to the reimbursement of amounts spent on these schemes in excess of the approved figure.

सीमेंट कारखानों की संख्या और उनका उत्पादन

5633. श्री राम किशन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सीमेंट के कुल कितने कारखाने हैं, उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा वास्तव में उनमें कितना उत्पादन हो रहा है ;

(ख) क्या वर्ष 1977-78 में नये सीमेंट कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने कारखानों के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) भारत में 55 सीमेंट फैक्टरियां हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 218.70 लाख मी० टन प्रति वर्ष है। वर्ष 1977 में सभी किस्मों की सीमेंट का 191 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था।

(ख) और (ग) : वर्ष 1977-78 में कुल चार औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, जिनमें से दो लाइसेंस राजस्थान को तथा एक-एक लाइसेंस मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश को जारी किया गया था।

Electrification of Villages in Ratnagiri District, Maharashtra

5634. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme for electrification of unelectrified villages in Ratnagiri District in Maharashtra has been submitted by Maharashtra State Electricity Board to Rural Electrification Corporation; and

(b) if so, what action has been taken so far on the said proposal?